संभाग पोस्ट

साप्ताहिक

RNI: MPHIN/2015/60688

जिलों से संभाग तक का सच

email:sambhagpost@gmail.com

वर्ष-10 । अंक-4 । प्रति मंगलवार, इंदौर, 30 जून 2026 से 06 जुलाई 2026 । । मूल्य- 2 रु. । पृष्ठ- 8

राज्य सूचना आयोग का ढोंग

संभाग पोस्ट ने अपने 23 जून 2026 के अंक में प्रमुखता से उठाया था मुद्दा

SPECIAL REPORT

✍नवीन गलकर

कागजों में पारदर्शिता धरातल पर प्रताड़ना..!

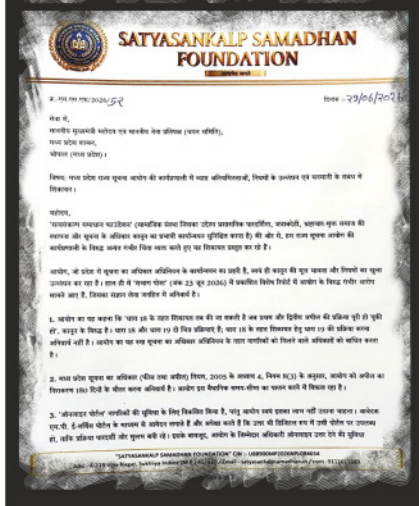

भोपाल/इंदौर। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का काम प्रदेश में पारदर्शिता की मशाल जलाए रखना और भ्रष्टाचार को बेनकाब करना है, आज वही आयोग स्वयं जवाबदेही के कटघरे में खड़ा है। 'संभाग पोस्ट' के पिछले अंक (23 जून 2026) में हमने 'प्रहरी ही बने अंधे' शीर्षक के साथ आयोग के कामकाज की पोल खोली थी। प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए अब 'सत्यसंकल्प समाधान फाउंडेशन' ने भी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, जनहित में अनिवार्य मानते हुए राज्य सूचना आयोग के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है फाउंडेशन ने (चयन समिति) मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष तथा राज्यपाल को शिकायत भेजकर इस 'अंधेरगर्दी' की जांच की मांग की है। (शेष पेज 4 पर)

सुविचार

'सफलता मन की शांति है, जो इस संतुष्टि का प्रत्यक्ष परिणाम है कि आपने अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास किया।'

संपादकीय

आस्था से छल

अयोध्या में राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिए दान और कीमती सामान की हेराफेरी की घटनाओं ने देश-विदेश के रामभक्तों को विचलित किया है। कभी आमजन में कहा जाता था कि 'भगवान से डर', लेकिन पैसे की हवस देखिए कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े चंद लोगों ने भगवान के घर में चोरी करने में कोई डर महसूस नहीं किया। ये प्रबंधन व व्यवस्था की पारदर्शिता की खोट तो है ही, मानवीय मूल्यों के पतन की पराकाष्ठा भी है कि मंदिर में चढ़ावे की देखरेख को तैनात लोग ही चोरी-चकारी में लिप्त हो जाएं। इस मामले में विपक्ष के तीखे हमले और जनाक्रोश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए आनन-फानन में एसआईटी गठित की, रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी, प्राथमिकी दर्ज की और वीरवार को प्रबंधन से जुड़े आठ कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन अपने आराध्य राम के चढ़ावे की चोरी से आहत भक्तों के जख्मों पर शायद तभी मरहम लगेगी, जब दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। निश्चित ही यह चोरी का प्रकरण भाजपा व संघ को परेशान करने वाला है। उस राजनीतिक दल के लिये, जिसके कभी दो सांसद हुआ करते थे और राम मंदिर की मुहिम से हासिल जनसमर्थन से केंद्र व तमाम राज्यों में उसकी सरकारें बनी हैं। खासकर, भाजपा के लिए यह मुद्दा परेशानी का सबब हो सकता है क्योंकि राम जन्म भूमि वाले प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जिस मुद्दे को लेकर भाजपा राज्य की सत्ता में आती रही है, उस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर होगा। निस्संदेह, इस प्रकरण से राम भक्तों की आस्था को गहरी चोट तो पहुंची है। सवाल राम मंदिर ट्रस्ट की नाकामी पर भी उठेंगे कि उसने समय रहते इस चोरी को क्यों नहीं पकड़ा। बेहतर होता कि दोषियों के खिलाफ ट्रस्ट की तरफ से स्वतः प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जाती। सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर क्यों ट्रस्ट चंदे की रकम का हिसाब-किताब विश्वसनीय तरीके से नहीं रख पाया। निश्चय ही इस प्रकरण से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की साख भी दांव पर लगी है। वह उन भक्तों की भावनाओं की रक्षा नहीं कर पाया, जिन्होंने मंदिर निर्माण से लेकर अब तक दिल खोलकर दान दिया। जब चंदा प्रबंधन से जुड़े लोगों के घर से लाखों की नकदी बरामद हुई और चोरी के पैसे से जमीन खरीदने के आरोप सामने आए तो भक्तों की आस्था पर आंच आना स्वाभाविक ही है। आरोप सिर्फ नकदी के हेरफेर के ही नहीं लगे बल्कि कीमती गहनों को खुर्दबुर्द करने के भी लगे। वहीं प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के दौरान दान में मिली चांदी की छड़ों के गायब होने का भी आरोप है। बहरहाल, 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले सामने आए इस विवाद ने प्रदेश में राजनीतिक हलचल मचा दी है। विपक्ष जहां दोषियों पर समय रहते कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहा है, वहीं भाजपा इन आरोपों को अयोध्या को बदनाम करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश बता रही है।

महानगर की कीमत पर मालवा का भविष्य नहीं...

इंदौर-उज्जैन महानगर क्षेत्र की दौड़ में कहीं मालवा की आत्मा तो नहीं खो रही...

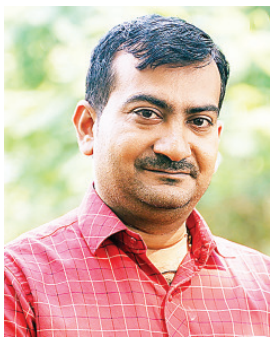

• **स्वप्निल व्यास, पर्यावरणविद**

इंदौर आज देश के सबसे तेज़ी से विकसित होते शहरों में गिना जाता है। महानगर बनने की महत्वाकांक्षा, मेट्रो रेल, सुपर कॉरिडोर, रिंग रोड, औद्योगिक विस्तार और अब इंदौर-उज्जैन महानगर क्षेत्र (Metropolitan Region) की अवधारणा सब कुछ विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। लेकिन इस चमकदार कहानी के पीछे एक ऐसा अध्याय भी लिखा जा रहा है, जिसे पढ़ने की फुर्सत शायद किसी के पास नहीं है। यह अध्याय है मालवा की मिट्टी, जल, जंगल, खेत और गांवों के अस्तित्व का। पिछले कुछ दिनों में महानगर क्षेत्र को लेकर लगातार चर्चाएं हुईं। कहीं कहा गया कि बिना महानगर बने विकास संभव नहीं, कहीं क्षेत्रीय मुख्यालय को लेकर बहस छिड़ गई। लेकिन इन बहसों में सबसे जरूरी प्रश्न गायब रहा क्या इस विकास की कीमत मालवा का पर्यावरण चुकाएगा? विकास का अर्थ केवल इमारतें नहीं होता। विकास वह होता है जो आने वाली पीढ़ियों को बेहतर जीवन दे। यदि विकास की कीमत पर नदियां मर जाएं, खेत कंक्रीट में बदल जाएं, जलस्रोत खत्म हो जाएं और गांव शहरों के उपनगर बनकर रह जाएं, तो यह विकास नहीं, भविष्य का विनाश है। मालवा का पूरा भूगोल जल संकट से जूझता रहा है। यहां की नदियां बारहमासी नहीं हैं। कान्ह, सरस्वती, गंभीर, क्षिप्रा जैसी नदियां पहले ही प्रदूषण और अतिक्रमण से कराह रही हैं। भूजल लगातार नीचे जा रहा है। ऐसे में लाखों नई आबादी, नए उद्योग और विशाल निर्माण कार्यों का बोझ इस धरती पर डालने से पहले क्या किसी ने उसकी जल धारण क्षमता का वैज्ञानिक आकलन किया है? आज शहरों का विस्तार जिस गति से हो रहा है, उससे सबसे अधिक नुकसान कृषि भूमि का हो रहा है। इंदौर के आसपास के गांव-तिल्लोर, बिलावली, लिम्बोदी, बिचौली, राऊ, सांवेर, हातोद और उज्जैन की दिशा तक फैली उपजाऊ जमीन धीरे-धीरे कॉलोनियों में बदल रही है। यह केवल जमीन का परिवर्तन नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा पर भी सीधा आघात है। विडंबना यह है कि विकास की योजनाओं में पर्यावरण को अक्सर 'क्लीयरेंस' तक सीमित कर दिया जाता है। पेड़ों की संख्या गिन ली जाती है, लेकिन जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र नहीं। तालाबों का नक्शा बना लिया जाता है, लेकिन उनके जलग्रहण क्षेत्र को नहीं बचाया जाता। नदियों को सीमेंट की दीवारों में कैद कर पुनर्जीवन का दावा किया जाता है, जबकि नदी केवल पानी की धारा नहीं, बल्कि जीवंत पारिस्थितिकी है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि महानगर क्षेत्र की योजनाओं में जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीरता दिखाई नहीं देती। मालवा पहले ही अनियमित वर्षा, बढ़ते तापमान और हीट वेव का सामना कर रहा है। हरियाली घट रही है और कंक्रीट का विस्तार 'हीट आइलैंड' प्रभाव को बढ़ा रहा है। यदि यही गति रही तो आने वाले वर्षों में इंदौर केवल स्वच्छ शहर नहीं, बल्कि अत्यधिक गर्म शहर भी बन सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किसी भी महानगर को स्थायी नहीं बना सकता। दुनिया के अनेक विकसित शहर अब 'ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर', 'ब्लू नेटवर्क', शहरी वन, नदी संरक्षण और कृषि क्षेत्र

बचाने की दिशा में लौट रहे हैं। जबकि हम उन्हीं गलतियों को दोहराने की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें दुनिया सुधारने में अरबों रुपये खर्च कर रही है। महानगर क्षेत्र का विरोध विकास का विरोध नहीं है। विरोध उस विकास मॉडल का है जो प्रकृति को बाधा मानता है। यदि वास्तव में इंदौर-उज्जैन क्षेत्र को भविष्य का आदर्श बनाना है तो सबसे पहले पर्यावरणीय मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए। हर परियोजना से पहले जल, भूमि, जैव विविधता और स्थानीय सामाजिक प्रभाव का समग्र अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। मालवा केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है; यह संस्कृति, कृषि, जल परंपरा और लोकजीवन का संगम है। यहां के तालाब, बावड़ियां, चरागाह, नदी मार्ग और खेती सदियों की प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का परिणाम हैं। इन्हें मिटाकर यदि केवल कंक्रीट का महानगर बनाया गया, तो भविष्य की पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। राजनीतिक बहसें मुख्यालय इंदौर में हो या उज्जैन में यह प्रशासनिक विषय हो सकता है। लेकिन असली मुख्यालय तो प्रकृति होनी चाहिए। यदि नदी नहीं बचेगी, खेत नहीं बचेंगे, भूजल नहीं बचेगा, तो किसी भी मुख्यालय का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आज आवश्यकता है कि महानगर क्षेत्र को 'वाट्रोपोलिटन' और 'ईको-मेट्रोपोलिटन' की अवधारणा के साथ विकसित किया जाए। हर नदी का जलग्रहण क्षेत्र सुरक्षित हो, हर तालाब का पुनर्जीवन हो, हर गांव की कृषि भूमि को अंधाधुंध भू-परिवर्तन से बचाया जाए और शहरी विस्तार की स्पष्ट पर्यावरणीय सीमा तय हो। विकास का वास्तविक अर्थ ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि ऊंचे विचार हैं। यदि मालवा का विकास उसकी मिट्टी, पानी और प्रकृति को बचाकर होता है, तभी यह सच्चा विकास होगा। अन्यथा इतिहास यही लिखेगा कि हमने महानगर बनाने की जल्दबाजी में मालवा की आत्मा खो दी।

आज समय की मांग है कि सरकार, जनप्रतिनिधि, नगर नियोजक, पर्यावरणविद् और समाज एक साथ बैठें। महानगर क्षेत्र की रूपरेखा केवल निवेश और निर्माण के आधार पर नहीं, बल्कि जल, जंगल, जमीन और जलवायु की वहन क्षमता के आधार पर तय हो। क्योंकि शहरों का भविष्य कंक्रीट नहीं, प्रकृति तय करती है।

मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने से पहले मास्टर प्लान पर ब्रेक, बढ़ रही अवैध बसाहट; विकास भी प्रभावित

■ इंदौर । नगर प्रतिनिधि

इंदौर शहर को सरकार महानगर बनाने की कवायद में जुटी है, लेकिन अभी तक इंदौर का मास्टर प्लान ही जारी नहीं हो सका। पिछले पांच वर्षों से नए मास्टर प्लान के बिना ही इंदौर फैल रहा है। इसके कारण शहरी सीमा से जुड़े इलाकों में बेतरतीब विकास हो रहा है। इंदौर का मास्टर प्लान मेट्रोपॉलिटन सिटी के चक्कर में ही अटका हुआ है।

अब तक प्रारूप ही प्रकाशित नहीं

अब माना जा रहा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी की अधिसूचना जारी होने के बाद मास्टर प्लान तैयार करने की शुरुआत हो सकती है। इसे लागू होने में दो से तीन साल का समय लग सकता है। खास बात यह है कि नया मास्टर प्लान वर्ष 2035 को ध्यान में रखकर बनाया जाना है, लेकिन इसे तैयार करने में ही नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने पांच साल लगा दिए। अभी तक इसका प्रारूप भी प्रकाशित नहीं हो पाया है।

तेजी से बढ़ रही अवैध बसाहट

सामाजिक संगठन इंदौर उत्थान के पदाधिकारियों ने इंदौर के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ मास्टर प्लान बनाने की मांग उठाई है, लेकिन अभी तक नया मास्टर प्लान तैयार नहीं हो पाया। इंदौर में प्रदेश की दूसरी इन्वेस्टर्स समिट वर्ष 2008 में हुई थी। उसी दौरान मास्टर प्लान लागू किया गया था। इसकी मियाद पांच साल पहले ही समाप्त हो चुकी है। नियमानुसार नया मास्टर प्लान लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसका कोई अता-पता नहीं है। इस बीच शहर की सीमा से लगे क्षेत्रों में अवैध बसाहट तेजी से बढ़ रही है। नए मास्टर प्लान के तहत शहर के 79 गांवों को शामिल करने की अधिसूचना जारी की गई है। इन क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की अनुमति भी फिलहाल नहीं मिल पा रही है।

विधानसभा में भी उठ चुका है मुद्दा

इंदौर और भोपाल के मास्टर प्लान में हो रही देरी का मुद्दा विधानसभा में भी उठ चुका है। विस में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल किया था कि इंदौर और भोपाल का मास्टर प्लान क्या बैलगाड़ी में आ रहा है? इसके जवाब में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि मास्टर प्लान जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।

पुराना मास्टर प्लान 60 प्रतिशत भी लागू नहीं

इंदौर में पिछला मास्टर प्लान 1 जनवरी 2008 को लागू किया गया था। इसे विकास योजना-2021 नाम दिया गया था। यह योजना 13 वर्षों के लिए बनाई गई थी, लेकिन 18 साल बाद भी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर सकी। मास्टर प्लान का 90 प्रतिशत कार्य भी पूरा नहीं हो पाया। शहर में न तो प्रस्तावित सभी सिटी फॉरेस्ट बन पाए और न ही सभी प्रमुख मार्ग पूरे हो सके। एमआर-3 और एमआर-4 आज भी अधूरे हैं, जबकि एमआर-11 और एमआर-12 का निर्माण भी पूरी तरह नहीं हो पाया है। रीजनल पार्क के अलावा केवल स्कीम-78 और बिचौली मर्दाना में सिटी फॉरेस्ट विकसित किए गए, जबकि मास्टर प्लान में 10 से अधिक उद्यान प्रस्तावित थे। वर्ष 2008 के मास्टर प्लान में नए ट्रेंचिंग ग्राउंड का भी प्रावधान था, लेकिन वह भी आज तक नहीं बन सका।

> मास्टर प्लान वर्ष 2035 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। मेट्रोपॉलिटन सिटी की अधिसूचना जारी होने के बाद इस काम में तेजी आने की उम्मीद है।
>
> *शंकर लालवानी, इंदौर सांसद*

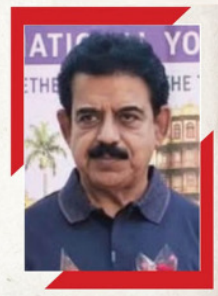

समय सीमा समाप्त हो चुकी : नारंग

इंदौर उत्थान के संयोजक अजीत सिंह नारंग का कहना है कि मास्टर प्लान एक निश्चित समय सीमा के लिए तैयार किया जाता है और इंदौर में उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। अब नया मास्टर प्लान बनकर तैयार हो जाना चाहिए, ताकि शहर के विस्तार और नई बसाहट को व्यवस्थित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ मास्टर प्लान की मांग को लेकर संगठन पहले भी अभियान चला चुका है।

हैदराबाद पुलिस की इंदौर में दबिश

साइबर ठगी के मामले में तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

■ इंदौर । नगर प्रतिनिधि

हैदराबाद में सामने आए एक बड़े साइबर ठगी मामले की जांच करते हुए हैदराबाद पुलिस ने इंदौर में दबिश देकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई पलासिया और खजराना थाना क्षेत्र में इंदौर पुलिस के सहयोग से की गई। गिरफ्तार आरोपियों को जिला न्यायालय में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद ले जाया गया है।

जानकारी के अनुसार, हैदराबाद में हुई साइबर ठगी की जांच के दौरान पुलिस को बैंक खातों के लेनदेन और कॉल डिटेल की जांच में तीन संदिग्ध युवकों का सुराग मिला। जांच में सामने आया कि संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और मोबाइल लोकेशन इंदौर से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद हैदराबाद पुलिस की टीम इंदौर पहुंची। इंदौर पहुंचने पर टीम ने सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी साझा की। इसके बाद पलासिया और खजराना थाना पुलिस के सहयोग से संयुक्त कार्रवाई करते हुए सुमित, तिलक और कपिल नामक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

खंडवा-बुरहानपुर के रहने वाले

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तीनों आरोपी मूल रूप से खंडवा और बुरहानपुर के निवासी हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से इंदौर के पलासिया और खजराना क्षेत्र में किराये के मकानों में रह रहे थे। पुलिस का दावा है कि साइबर ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों और मोबाइल नंबरों का संबंध इन्हीं आरोपियों से मिला है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को इंदौर जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद हैदराबाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। अब वहां उनसे पूछताछ कर साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क और अन्य संभावित आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी।

बड़े नेटवर्क के खुलासे की संभावना

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। पूछताछ के दौरान साइबर ठगी से जुड़े बड़े गिरोह, फर्जी बैंक खातों और अन्य राज्यों तक फैले नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। इंदौर पुलिस ने भी जांच में पूरा सहयोग किया है। आने वाले दिनों में इस मामले में और अहम खुलासे हो सकते हैं।

आरटीओ इंदौर द्वारा पाँच यात्री बसें जब्त

■ इंदौर । नगर प्रतिनिधि

परिवहन आयुक्त श्री उमेश जोगा और इंदौर कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देश पर आरटीओ इंदौर और संभागीय परिवहन उड़नदस्ता इंदौर ने यात्री बसों और अन्य वाहनो के विरुद्ध कार्यवाही कर पाँच यात्री बसे जब्त की । आरटीओ द्वारा तीन इमली चौराहे पर यात्री वाहनों की सघन जांच की गई। जांच में वाहनो के परमिट ,फिटनेस ,बीमा सहित सभी दस्तावेज चेक किये गए। वाहनों का निरीक्षण भी किया गया जिसमें चेक किया गया की वाहन फिटनेस शर्तो, परमिट शर्तों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। फायर सेफ्टी उपकरण ,स्पीड गवर्नर सही से काम तो कर रहे है। साथ ही यात्रियों से फीडबैक भी लिया गया की वाहन चालक, वाहन को तेज गति से तो नही चलाते है, या वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग तो नहीं करते है। उक्त कार्यवाही आरटीओ प्रदीप शर्मा,परिवहन उड़नदस्ता प्रभारी आकाश सिटोले द्वारा की गई इसके साथ ही बताया कि यात्री बसों और स्कूल/शैक्षणिक संस्था बसों में सुरक्षा मानको की पूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु इंदौर जिले में स्थित स्कूली/कॉलेज के वाहनों की आक्समिक चेकिंग अभियान निरंतर जारी रहेगा।

(प्रथम पेज का शेष)

आपको बता दें 'सत्यसंकल्प समाधान फाउंडेशन' एक सामाजिक संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करना है। साथ ही, यह संस्था सूचना के अधिकार कानून के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करती है।

फाउंडेशन का आरोप है कि आयोग सूचना के अधिकार कानून की मूल भावना के विपरीत कार्य कर रहा है। फाउंडेशन के अनुसार, आयोग का यह कहना कि 'धारा 18 के तहत शिकायत तब तक नहीं की जा सकती जब तक प्रथम और द्वितीय अपील की प्रक्रिया पूरी न हो जाए', कानून के प्रावधानों के विरुद्ध है। धारा 18 और धारा 19 दो स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, जिन्हें आयोग अनावश्यक रूप से जोड़कर नागरिकों के अधिकारों को बाधित कर रहा है। शिकायत में इस बात पर भी गहरा रोष व्यक्त किया गया है कि राज्य सूचना आयोग के पास ऑनलाइन पोर्टल होने के बावजूद अधिकारी जानबूझकर डाक के माध्यम से उत्तर भेज रहे हैं। डिजिटल इंडिया के इस युग में, जब सब कुछ ऑनलाइन सुलभ है, आयोग के अधिकारी जानबूझकर डाक से जवाब भेजकर आवेदकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। फाउंडेशन का कहना है कि यह पुरातनवादी सोच डिजिटल इंडिया के दावों का मखौल उड़ा रही है। इसके अलावा, पोर्टल पर प्रदर्शित लोक सूचना अधिकारियों के नंबरों का काम न करना, सुनवाई की स्थिति अपडेट न होना और वार्षिक प्रतिवेदन का अद्यतन न होना आयोग की पारदर्शिता पर बड़े प्रश्नचिह्न खड़े करता है।

फाउंडेशन ने 'संभाग पोस्ट' की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्य सूचना आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। संस्था ने लोक सूचना अधिकारी ज्योति मोडक द्वारा दी जा रही झूठी जानकारी और आयोग द्वारा उन पर कार्यवाही करने के बजाय मामले को रफा-दफा करने के प्रयासों की कड़ी निंदा की है। संस्था ने मांग की है कि आयोग अपनी वेबसाइट को अद्यतन करे, पूर्णतः डिजिटल प्रणाली अपनाए और सूचना के अधिकार (फीस तथा अपील) नियम, 2005 का अक्षरसः पालन सुनिश्चित करे।

संभाग पोस्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव की कार्यप्रणाली पर भी अपीलार्थियों को सहयोग न मिलने को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए गए थे। क्या मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव की चुप्पी इस तानाशाही को मौन सहमति नहीं है?

आयोग की शिकायतें मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और राज्यपाल तक पहुँच चुकी हैं। अब देखना यह है कि क्या उच्च पदों पर आसीन ये पदाधिकारी जनसामान्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 'सूचना का अधिकार' कानून का प्रदेश में प्रभावी पालन सुनिश्चित करा पाएंगे, या स्थिति 'ढाक के तीन पात' वाली ही बनी रहेगी?

संभाग पोस्ट सामाजिक दृढ़ता संकल्प अभियान

अब आपकी आवाज होगी बुलंद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के संग

आज के समाज में हम देख रहे हैं की शहरी परिवेश की बात करें या ग्रामीण परिवेश की आज के परिवेश में व्यक्ति अकेला पड़ता जा रहा है। आधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल करते-करते अपने आप को अकेला महसूस करता है , जब उसके ऊपर ऐसी कोई विपत्ति आती है की जब उसके परिवारजन या मित्र बंधु उसका साथ दे। तब वह पता है कि वह अकेला खड़ा है। यह आज के समाज का सत्य है। यह भारत के ७० प्रतिशत लोगों की सच्चाई है वह किसी भी प्रकार की समस्या में हो चाहे पारिवारिक या मानसिक, सामाजिक, प्रशासनिक या चिकित्सकीय हो ऐसी किसी भी समस्या में वह पाता है कि वह अकेला है। और यदि ऐसे मे किसी मोड़ पर कुछ व्यवधान उत्पन्न हो तब वह नीरस हो जाता है, और किसी न किसी प्रकार की गलती कर बैठता है । समाज की ऐसी सबसे बड़ी समस्या को लेकर हमने सामाजिक दृढ़ता संकल्प का अभियान चलाया है जिसके तहत हम उन सभी ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए हैं जो हमसे जुड़ेंगे तथा वे लोग जो हमसे किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं , हमारा प्रयास यह होगा कि ऐसी किसी भी समस्या में हम उनके साथ खड़े हो जिस जगह पर वह सही है और उन्हें व्यवधान,समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में संभाग पोस्ट परिवार उनके साथ खड़ा है।

- समाज में एक कहावत प्रचलित है सत्य परेशान हो सकता है। पराजित नहीं हो सकता,
- ईश्वर की इसी प्रेरणा को हमारे मीडिया चैनल हमारे अखबार ने आत्मसात किया है और हम उन सभी समाज जनों के साथ खड़े हैं जिनके साथ सत्य है।
- ईश्वर सत्य का साथ देने वाले उनके अनुयायियों की सहायता करने स्वयं नहीं आते किंतु किसी न किसी माध्यम से सत्य का साथ दे रहे व्यक्ति की सहायता जरूर करते हैं।
- हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमने यह मुहिम चलाई है जिसके तहत यदि आपके साथ सत्य है तो हम आपके साथ सदा खड़े हुए हैं
- हमारे चैनल और हमारे अखबार से जुड़े हुए सभी सदस्य गण जिनकी किसी भी प्रकार की परेशानी अब उनकी नहीं वह हमारी है।
- जब समाज दृढ़ होगा, सत्य की विजय होगी जब एकता और समान व्यवहार और ज्ञान होगा तब हमारा समाज एक नए भारत का दृढ़ निश्चय भारत का निर्माण कर पाएगा
- यदि आपका काम, स्वयं आप और आपका विचार, सत्य के साथ है तो वह आपका नहीं अपितु वह हमारा विचार होगा , क्योंकि आप भारत के चौथे स्तंभ मीडिया के साथ है
- अब आम आदमी की आवाज आम आदमी की नहीं अपितु उसके साथ हमारी भी आवाज होगी इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे साथ शीघ्र से शीघ्र जुड़े और अपनी आवाज को एक नया आयाम दें और अपने समाज को अपने परिवार को और अपने देश को सशक्त बनाएं
- हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको कोई नया प्रयास नहीं करना केवल सामाजिक दृढ़ता संकल्प संभाग पोस्ट अभियान का एक फॉर्म भरना है

विचार न कीजिए तुरंत संपर्क करें: 9755648321

क्योंकि दृढ़ होगा समाज तो सशक्त होगा भारत और खुशहाल होगा हमारा परिवार

सत्यम,शिवम्,सुंदरम। सत्यमेव जयते

भारत माता की जय वंदे मातरम

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान से सियासी हलचल तेज

'हर अधिकारी खुद को संघ का स्वयंसेवक बता रहा'

संघ में अब भीड़ हो गई है। हमारी संख्या बढ़ गई है और हम एक बहुत बड़ा संगठन बन गए हैं। अब सरकार में शामिल होने वाला कोई भी अधिकारी कहता है कि मैंने भी संघ की पट्टी और चड्डी पहनी है। जब से बीजेपी सरकार बनी है, सभी अधिकारी संघ के समर्थक बन गए हैं। एक अधिकारी ने मुझसे कहा कि मेरे पिता संघ की बैठकों में जाते थे। दूसरे ने कहा, मेरे पिता संघ के अध्यक्ष थे।

- कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी नेता

• इंदौर । विशेष प्रतिनिधि

मध्यप्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद कई अधिकारी और कर्मचारी खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ा बताने लगे हैं। भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विजयवर्गीय ने कहा कि जब भी कोई अधिकारी उनसे मिलने आता है, वह किसी न किसी रूप में संघ से अपने या अपने परिवार के जुड़ाव का उल्लेख करता है। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि कोई बताता है कि वह बचपन में शाखा में जाता था, कोई कहता है कि उसने शाखा में पट्टी और बेल्ट बांधी है, जबकि कुछ अधिकारी अपने पिता के संघ से जुड़े होने का जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे सरकार बनने के बाद हर अधिकारी और कर्मचारी स्वयं को संघ का स्वयंसेवक साबित करने में लगा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि संगठन का विस्तार होना सकारात्मक बात है, लेकिन इसके साथ अच्छे और संस्कारित लोगों की संख्या बढ़ना भी उतना ही आवश्यक है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि किसी भी विचारधारा की वास्तविक ताकत उसके कार्यकर्ताओं और उनसे जुड़े लोगों के आचरण में दिखाई देती है। यदि समाज में अच्छे और संवेदनशील लोगों की कमी होगी, तो केवल संगठन के विस्तार से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उन्होंने इस विषय पर आत्ममंथन और गंभीर चिंतन की आवश्यकता भी बताई।

यह मामला भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की निष्पक्षता का है'

उधर, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 'एक्स' पर विजयवर्गीय के बयान का वीडियो साझा करते हुए कहा कि यह मामला भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की निष्पक्षता, तटस्थता और संवैधानिक गरिमा से जुड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। पटवारी ने कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक सरकारी अधिकारी से केवल संविधान के प्रति निष्ठा की अपेक्षा करता है, किसी राजनीतिक या वैचारिक संगठन के प्रति नहीं। उन्होंने राष्ट्रपति और मध्य प्रदेश के राज्यपाल से इस मामले को संज्ञान में लेकर संवैधानिक समीक्षा कराने की मांग भी की।

जितेंद्र जैन यशवंत क्लब के नए अध्यक्ष पम्मी छाबड़ा को 65 वोट से हराया

■ इंदौर । नगर प्रतिनिधि

इंदौर के प्रतिष्ठित क्लबों में शामिल यशवंत क्लब के रविवार को हुए चुनाव में उलटफेर हो गया। पांच हजार से अधिक सदस्यों वाले इस क्लब के अध्यक्ष पद के जितेंद्र जैन चुन गए। उन्होंने पम्मी छाबड़ा को 65 वोटों से हरा दिया। वहीं, विजय कस्तुरी ने अतुल सेठ को 43 वोट से हराकर सचिव पद पर जीत पाई। टीम हैप्पी वाईसी ने तगड़ी जीत हासिल की। टीम के अध्यक्ष व सचिव के अलावा सहसचिव तेजवीर जुनेजा और कोषाध्यक्ष रूपल एम पारेख चुने गए हैं। जीतू जैन की पैनल ने पहले राउंड से ही बढ़त बना ली थी, जो अंतिम राउंड तक कायम रही।

मुख्य मुकाबला परमजीत सिंह पम्मी छाबड़ा और जितेंद्र जैन के बीच थी। पम्मी छाबड़ा पहले भी क्लब के अध्यक्ष रह चुके हैं, जबकि जितेंद्र जैन गौरानी-सचदेवा पैनल के समर्थन से चुनाव मैदान में थे। वे पहली बार अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने शुरुआती दौर से ही बढ़त बना ली थी। गौरानी-सचदेवा पैनल के ज्यादातर उम्मीदवार चुनाव जीत गए।

मतदान सुबह 9 बजे शुरू हुआ। इसमें बड़ी संख्या में सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह से ही क्लब परिसर में मतदाताओं की आवाजाही शुरू हो गई थी। उम्मीदवारों के समर्थक हाथों में तख्तियां लेकर उन्हें जिताने की अपील कर रहे थे।

छाबड़ा पैनल से अतुल शेठ को सचिव पद का उम्मीदवार बनाया गया था, उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। शाम चार बजे तक मतदान चला। इसके बाद मतगणना शुरू हुई। शुरुआत से ही अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जितेंद्र जैन ने बढ़त बनाए रखी, जो अंत तक कायम रही। रात को जब चुनाव के परिणाम आए तो गौरानी-सचदेवा पैनल के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। सदस्यों ने क्लब की गतिविधियों में किए जा रहे बदलाव, नए निर्माण सहित अन्य फैसलों पर अपने वोट देकर समर्थन दिया। छाबड़ा पैनल ने नए सदस्यों को क्लब में शामिल करने का मुद्दा इस बार चुनाव में उठाया था।

काव्य कुँअर और काव्य दीप सम्मान समारोह 1 जुलाई को

कवि देवकृष्ण व्यास को मिलेगा स्वर्णाक्षर सम्मान

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

कीर्तिशेष डॉ. कुँअर बेचैन जी की जन्म जयंती निमित्त मातृभाषा उन्नयन संस्थान व डॉ. कुँअर बेचैन स्मृति न्यास, ऑस्ट्रेलिया द्वारा काव्य कुँअर व काव्य दीप सम्मान समारोह का आयोजन बुधवार, 1 जुलाई 2026 को दोपहर को 3 बजे से प्रीतमलाल दुआ सभागार में किया जा रहा है। डॉ. कुँअर बेचैन की जन्म जयंती पर प्रतिवर्षानुसार मंचीय कवियों का सम्मान किया जाएगा, साथ ही, स्वर्णाक्षर सम्मान से वरिष्ठ कवि को सम्मानित किया जाएगा। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अर्पण जैन ने बताया कि 'संस्थान विगत पाँच वर्षों से लगातार डॉ. कुँअर बेचैन जी की जन्म जयंती पर काव्य कुँअर का आयोजन कर रहा है। इसी अवसर पर इस वर्ष चौथी पीढ़ी के कवियों को काव्य दीप सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन में हिन्दी आंदोलन, हिन्दीग्राम व मातृभाषा डॉट कॉम के सहयोग से सर्जना का सम्मान होगा।'

डॉ. कुँअर बेचैन स्मृति न्यास के अध्यक्ष प्रगीत कुँअर ने बताया कि 'पूज्य पिताश्री व सुप्रसिद्ध कवि डॉ. कुँअर बेचैन जी की स्मृतियाँ अक्षर के रूप में लाखों लोगों तक प्रसारित रखने के उद्देश्य से न्यास लगातार प्रयत्नशील हैं, कविता परम्परा का निर्वहन डॉ. बेचैन जी को सच्ची श्रद्धांजलि है।'

कार्यक्रम में देवास निवासी सुप्रसिद्ध राष्ट्रवादी देवकृष्ण व्यास को स्वर्णाक्षर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।

काव्य दीप सम्मान से ये होंगे सम्मानित: काव्य दीप सम्मान से सम्मानित होने वाले मंचीय कवियों में उज्जैन से प्रशांत व्यास 'रुद्र', फ़तेहपुर से सुंदरम फ़तेहपुरी, नरसिंहपुर से मेघा मिश्रा, बालाघाट से माही शुक्ला, बालाघाट, आष्टा से अंकित शर्मा, मंदसौर से अभिषेक सोलंकी व सुभाष बोराना, सनावद से गौरव पटेल नीलकंठ व श्रीधरा पटेल, सोनगढ़ से नारायण कुमावत, सिवनी से राज तेकाम, कसरावद से गौतम रावल, टोकसर से अजय वर्मा एवं इंदौर से प्रशांत राव चौरसे, हिमांशु मंगला वर्मा, पवन जोशी, कुलश्रेष्ठ शर्मा, प्राची शर्मा, निशिका नागर, डॉ. आभांश शर्मा, गोपाल सोलंकी इंदौरी, विशाल शर्मा 'जानिब' व यश शुक्ला शामिल हैं। आयोजन सभी के लिए खुला है।

मध्य प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने शुरू की प्रमोशन की तैयारी, 29 जून को बुलाई 20 विभागों की बैठक

■ **भोपाल । संभाग पोस्ट**

मध्य प्रदेश के करीब 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। हाईकोर्ट में लंबे समय से लंबित पदोन्नति विवाद के बावजूद, राज्य सरकार ने राज्य में प्रमोशन की रुकी हुई प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्य सचिव के कड़े निर्देशों के बाद सामान्य प्रशासन विभाग पूरी तरह एक्टिव हो गया है। विभाग ने आगामी 29 जून को 20 प्रमुख विभागों के अधिकारियों की एक हाई-लेवल बैठक बुलाई है, ताकि क्रेडर डिटेल्स और प्रमोशन के मानदंडों को अंतिम रूप दिया जा सके।

साल 2016 से अटका है मामला

मध्य प्रदेश में साल 2016 से प्रमोशन की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में लंबित आरक्षण विवाद के कारण पूरी तरह ठप पड़ी थी। गतिरोध को तोड़ने के लिए सरकार ने 17 जून 2025 को 'मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025' को मंजूरी दी थी। हालांकि, इसे जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाल ही में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली है, जिन्होंने हरी झंडी देते हुए कहा है कि क्योंकि हाईकोर्ट ने नए नियमों पर कोई सीधा स्टे नहीं लगाया है, इसलिए सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है।

कर्मचारी संगठनों ने खड़े किए सवाल

सरकार के इस कदम से जहां युवाओं के लिए नए रोजगार और भर्ती के रास्ते खुलेंगे, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी संगठनों ने इस पर तीखी आपत्ति दर्ज कराई है। संगठनों का कहना है कि सरकार ने पहले कोर्ट को कुछ और आश्वासन दिया था।

विभागों को निर्देश: सभी 20 विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 29 जून की बैठक में अपने क्रेडर, स्वीकृत पदों, प्रमोशन की योग्यताओं और खाली पदों का पूरा ब्योरा लेकर आएं।

असर: इस फैसले से न केवल प्रशासनिक स्तर पर खाली पद भरे जाएंगे, बल्कि पिछले एक दशक से अपनी बारी का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है।

जिंदा बुजुर्ग को रिश्तेदारों ने बताया मृत!

फर्जी डेथ सर्टिफिकेट से करोड़ों की जमीन बेचने का खेल बेनकाब

■ **इंदौर । संभाग पोस्ट**

राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां रहने वाली बुजुर्ग द्रोपदी बाई ने पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई कि राजेंद्र नगर क्षेत्र में उनकी करोड़ों रुपये की जमीन है, लेकिन कुछ रिश्तेदारों ने उन्हें कागजों में मृत घोषित कर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उनकी जमीन अपने नाम कराने और उसे दूसरे लोगों को बेचने का प्रयास किया।

फर्जी डेथ सर्टिफिकेट से जमीन हड़पने की साजिश

बुजुर्ग महिला को जब इस पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल पुलिस से शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने विभिन्न स्तरों पर जांच-पड़ताल की। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने द्रोपदी बाई की शिकायत के आधार पर 13 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।

जांच में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा

एडिशनल पुलिस कमिश्नर मयंक अवस्थी ने बताया कि जांच के दौरान यह सामने आया कि महिला के परिजनों ने फर्जी तरीके से उनका मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराया था। इसी दस्तावेज का उपयोग जमीन के नामांतरण (म्यूटेशन) की प्रक्रिया में किया गया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र किसने और किस प्रक्रिया के तहत तैयार किया।

29 साल बाद दर्ज हुआ मामला

पुलिस के अनुसार, इस पूरे मामले की गहन जांच के बाद लगभग 29 साल बाद प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच में कई अहम तथ्य सामने आए हैं और संभावना है कि आने वाले दिनों में कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

13 आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी निगाहें

फिलहाल पुलिस ने 13 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है। वहीं, इस पूरे मामले ने जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े और दस्तावेजों के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मप्र के 253 पुल जर्जर, 46 सबसे खतरनाक घोषित

सुरक्षा ऑडिट अधूरा, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

■ **भोपाल । संभाग पोस्ट**

मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के रिकॉर्ड में प्रदेश के 253 पुल जर्जर श्रेणी में चिन्हित किए जा चुके हैं। इनमें से 46 पुलों की स्थिति बेहद खतरनाक बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी हर वर्ष पुलों और पुलियों के सुरक्षा ऑडिट की सिफारिश करती रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में कई स्थानों पर भौतिक निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है।

46 पुलों को माना गया सबसे ज्यादा जोखिम वाला

पीडब्ल्यूडी की सूची के अनुसार प्रदेश में 253 पुल मरम्मत और निगरानी की जरूरत वाली श्रेणी में हैं। इनमें 46 पुल ऐसे हैं, जिन्हें अत्यधिक संवेदनशील और जोखिमपूर्ण माना गया है। ऐसे पुलों पर दुर्घटना की आशंका को देखते हुए नियमित निगरानी और मरम्मत की आवश्यकता बताई गई है।

निरीक्षण के साथ फोटो अपलोड करना अनिवार्य

नियमों के मुताबिक वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलों के फाउंडेशन, बियरिंग्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स और जल निकासी की स्थिति की जांच की जाती है। इंजीनियरों को निरीक्षण रिपोर्ट विभागीय सॉफ्टवेयर पर तस्वीरों सहित अपलोड करना अनिवार्य है। हालांकि विभाग का कहना है कि इस वर्ष की कई रिपोर्टें अभी आना बाकी हैं।

डॉ. हिमांशु केलकर
एम.डी., डी.सी.एच.
नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ
मो. 9202238451
क्लिनिक: 20 जी/एच., गीतांजलि अपार्टमेन्ट, मार्केट रोड, विजय नगर
स्कीम नं. 54, इंदौर (म.प्र.) Email : himanshukelkar@rediffmail.com
समय : प्रातः 10.30 से 1.30 बजे, सायं 5.30 से 8.30 बजे तक
निवास : 7-बी, शालीमार टाउनशिप, ए.बी. रोड, इंदौर

श्री रवि इत्र सुगन्ध भण्डार
गुलाब, मोगरा, चन्दन, परफ्यूम इत्यादि के थोक एवं खेरची विक्रेता
प्रोपायटर : रवि सुगन्धी
मो. 9452665448
पता: हीरानगर, मेनरोड, सुखलिया, मिलन गार्डन के पास, इन्दौर

AFSL SERVICES INDIA LLP
Registered Under Ministry of Corporate Affairs & MSME, Govt of India
An ISO 9001: 2015 Certified Forensic Science Laboratory, LLPIN: ACN-6724
FORENSIC SCIENCE SERVICES
Scientific Assistance Towards Justice
• Crime Scene Investigation
• Handwriting, Signature & Documents Examination
• Fingerprint Examination
• Audio & Video Examination
• Voice Examination
• Computer/Cyber Crime Investigation
• Fire & Arson Investigation
• Insurance Fraud Investigation
• 65B IEA Certificate [63(4)(c) BSA]
• Cross Examination of forensic experts and reports
• Forensic Training & Internship
• Medicolegal Consultancy
• Photography Examination
• Forensic Consultancy.
www.appliedforensicresearchsciences.in

संदीप पवार
Mob :-98260-68380
KP
॥ श्री गणेशाय नमः॥
न्यू नर्मदा ट्रेडर्स
सीमेन्ट
बालू रेती
काली रेती, गिट्टी
ईंट एवं बिल्डिंग मटेरियल के विक्रेता
4, मंगलनगर, आई.टी.आई. रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, पेट्रोल पम्प के पहले, इन्दौर (म.प्र.)

रामसेवक दुबे
9406621084
पूजा
बुक्स एण्ड स्टेशनर्स
CBCE स्कूल बुक्स
चिल्ड्रन बुक्स
ऑफिस स्टेशनरी
कम्प्यूटर स्टेशनरी
स्कूल स्टेशनरी एवं
गिफ्ट आयटम
6/3, सुंदर अपार्टमेन्ट, क्लर्क कालोनी चौराहा, श्री सत्य सांई बाल विनय मंदिर के सामने, इन्दौर मो

राहुल जनरल स्टोर्स
शॉप नं. 3 मालवा मिल चौराहा, इंदौर
मो. 9977732802

राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर डही में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ

जनप्रतिनिधियों एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ने बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाकर किया अभियान का आगाज़

■ डही । संभाग पोस्ट

राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डही में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। अभियान का शुभारंभ नौनिहाल बच्चों को पोलियो रोधी दवा की दो बूंद पिलाकर किया गया। इस अवसर पर पार्षद एवं मंडल महामंत्री श्री शैलेंद्र सोनी, पार्षद श्री मंसूर सिद्दीकी, भूतपूर्व बीएमओ डॉ. जगदेव सिंह पवार, बीएमओ डॉ. जगदीश पटेरिया तथा मेडिकल ऑफिसर डॉ. राम सिंह इकवाले ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने 0 से 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को पोलियो की दवा की खुराक अवश्य पिलाएं। उन्होंने कहा कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम समय-समय पर बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाना है। उन्होंने सभी नागरिकों से इस जनहितकारी अभियान में सक्रिय सहयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि 'हर बच्चे तक पोलियो की दो बूंद पहुँचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।' अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमें निर्धारित माइक्रोप्लान के अनुसार प्रत्येक बूथ एवं घर-घर पहुँचकर पात्र बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी, ताकि कोई भी बच्चा इस जीवनरक्षक दवा से वंचित न रहे और पोलियो मुक्त भारत के संकल्प को और अधिक मजबूती मिल सके। कार्यक्रम में बीपीएम अर्चना जमरा, बीईई कन्हैयालाल भावसार, बीसीएम आनंद मुवेल, समस्त बूथ दल सदस्य, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अभियान के सफल संचालन हेतु सभी स्वास्थ्य कर्मियों को निर्धारित कार्ययोजना के अनुरूप प्रत्येक पात्र बच्चे तक पहुँच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे अपने आसपास के सभी बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य दिलवाएं और इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में सहभागी बनें।

इंदौर में ऑनर किलिंग के मामले में छह आरोपियों को हुई उम्रकैद, मृतक की पत्नी पलट गई थी बयान से

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

लव मैरिज के विवाद में युवक की हत्या (ऑनर किलिंग) के मामले में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद मिश्र ने छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला कोर्ट में आठ वर्षों तक चला। सभी गवाहों और पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। लड़की के परिजन इस शादी से खुश नहीं थे और उन्होंने युवक की हत्या कर दी। युवक की पत्नी और एक अन्य गवाह अपने बयानों से मुकर गए, लेकिन कोर्ट ने अन्य साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई।

कोर्ट ने हत्या के मामले में अरुण भालसे, शिवराम भालसे, राहुल पंवार, सोनू दांगे, राजेश मोये और विशाल खेडेकर को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास तथा हत्या के प्रयास के मामले में सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2018 में तेजकरण ने रिंकी भालसे से प्रेम विवाह किया था। इससे नाराज रिंकी के परिजनों और उनके साथियों ने तेजकरण पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बीच-बचाव करने आए मोनू पर भी जानलेवा हमला किया गया था। मुकदमे के दौरान मृतक की पत्नी रिंकी और घायल मोनू अपने बयानों से मुकर गए, लेकिन अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती आरती भदौरिया ने अन्य साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए सभी आरोपियों को हत्या और हत्या के प्रयास का दोषी ठहराते हुए दंडित किया।

ओंकारेश्वर में पहाड़ी से गिरा मलबा, चार दुकानें क्षतिग्रस्त; जानें किस वजह से टला बड़ा हादसा?

■ ओंकारेश्वर । संभाग पोस्ट

तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच रविवार रात एक बड़ा हादसा टल गया। ब्रह्मपुरी क्षेत्र में झूला पुल मार्ग स्थित राठौर धर्मशाला के नीचे चढ़ाई के पास रात करीब 11:20 बजे पहाड़ी से अचानक भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क पर आ गिरे। मलबे की चपेट में आने से रवि केवट, प्रवीण केवट, अरुण केवट सहित एक अन्य दुकानदार की चार दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। दुकानों में रखा सामान भी मलबे में दब गया, जिससे दुकानदारों को हजारों रुपये का नुकसान हुआ।

यहां दिनभर भारी भीड़ रहती है

अच्छी बात ये रही है यह घटना उस समय हुई, जब सभी दुकानें बंद हो चुकी थीं और

दुकानदार अपने-अपने घर जा चुके थे। यदि यह हादसा दिन में या श्रद्धालुओं की आवाजाही के दौरान होता, तो बड़ी जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता था। रात्रि की वजह से बड़ा हादसा टल गया। झूला पुल मार्ग तीर्थयात्रियों का प्रमुख मार्ग होने के कारण यहां दिनभर भारी भीड़ रहती है।

घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल प्रशासन को सूचना दी।

पहाड़ी से मलबा खिसककर सड़क पर आ गया

सोमवार सुबह नगर परिषद ओंकारेश्वर की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से मलबा हटाने का कार्य शुरू कराया। सीएमओ मोनिका पारधी ने बताया कि अत्यधिक वर्षा के कारण पहाड़ी से मलबा खिसककर सड़क पर आ गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। उन्होंने बताया कि नगर परिषद लगातार संवेदनशील स्थानों की निगरानी कर रही है तथा जहां खतरे की आशंका है, वहां चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों से अपील की कि वर्षा के दौरान पहाड़ियों और ढलानों के समीप अनावश्यक रूप से न रुकें तथा प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। पीड़ित दुकानदारों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा और आर्थिक सहायता देने की मांग की है। उनका कहना है कि वे छोटे और गरीब व्यापारी हैं तथा दुकान में रखा अधिकांश सामान मलबे में दबकर खराब हो गया है।

तलावली चांदा तालाब पर कर लिया था कब्जा, निगम ने तोड़ी 14 पक्की दुकानें

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

इंदौर के तालाबों पर वर्षों से अतिक्रमण होता रहा है, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण तालाबों में पानी आने का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो गया। इंदौर के तलावली चांदा तालाब पर अतिक्रमणकारियों ने लगभग 100 मीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची पक्की दीवार बना ली थी। इसके अलावा वहां निर्माण की तैयारी भी चल रही थी। साथ ही, 14 पक्की दुकानें भी बना ली गई थीं। अधिकारियों तक शिकायत पहुंचने पर पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए। नोटिस के बावजूद कब्जे नहीं हटाए गए तो सोमवार सुबह नगर निगम का अमला जेसीबी और श्रमिकों के साथ मौके पर पहुंचा। कार्रवाई के दौरान 14 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया तथा पक्की दीवार भी तोड़ दी गई। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बताया कि अवैध कब्जों को चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है, ताकि तालाबों का मूल स्वरूप सुरक्षित रहे और वर्षा जल के प्राकृतिक प्रवाह में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

उन्होंने बताया कि तलावली चांदा तालाब में पिछले कुछ वर्षों से पानी कम भर रहा था। अब तालाब में पानी लाने वाले प्राकृतिक चैनलों की भी सफाई कराई जाएगी। नगर निगम अधिकारियों ने शहर के अन्य तालाबों के आसपास भी अतिक्रमण चिन्हित किए हैं, जिन्हें हटाया जाएगा।

सिरपुर तालाब का किया निरीक्षण

नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने सोमवार को सिरपुर तालाब का भी निरीक्षण किया। बारिश के दौरान तालाब का पानी आसपास की बस्ती के कुछ घरों में घुस जाता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निचले हिस्से में वर्षा जल निकासी की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए तथा जिस मार्ग से पानी निकलता है, उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाए, ताकि पानी तेजी से निकासी कर

सके।इसके बाद उन्होंने कबीटखेड़ी स्थित 120 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का भी निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

इंदौर में नई नेता प्रतिपक्ष के पदभार ग्रहण से पहले पुलिस ने भाई को किया गिरफ्तार

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

इंदौर में कांग्रेस ने चिंटू चौकसे को हटाकर सोनाली मिमरोट को नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है। सोमवार को उनके पदभार ग्रहण का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन इससे पहले ही उनके भाई बादशाह मिमरोट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ पंढरीनाथ थाने में एक राजनीतिक आंदोलन के दौरान हुए विवाद के मामले में प्रकरण दर्ज था। रविवार रात पुलिस उनके घर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि कुछ दिन पहले कलेक्टर कार्यालय पर महिला कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र

भाषा का प्रयोग किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें एसीपी कोर्ट में पेश किया।

यह है मामला

कुछ दिन पहले महिला कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। मौके पर पुलिस बल भी तैनात था। इसी दौरान बादशाह मिमरोट का पुलिसकर्मियों से विवाद हो गया। इस दौरान एक कांग्रेस नेत्री द्वारा पुलिसकर्मियों के लिए अपशब्द कहे जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। जांच के दौरान बादशाह मिमरोट की भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें भी मामले में आरोपी बनाया। सोनाली मिमरोट का कहना है कि उनका भाई उनके पदभार ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुटा था। उन्हें बेवजह इस मामले में फंसाया गया है और गिरफ्तारी के लिए जानबूझकर सोमवार का दिन चुना गया। गौरतलब है कि करीब दो महीने पहले भाजपा कार्यकर्ताओं के गांधी भवन पर हुए प्रदर्शन के दौरान पथराव की घटना में भी सोनाली मिमरोट का पुलिसकर्मियों से विवाद हुआ था।

इंदौर के फूटी कोठी में मकान में भीषण आग, चार लोगों को सुरक्षित निकाला

■ इंदौर । नगर प्रतिनिधि

इंदौर के फूटी कोठी चौराहे के पास रविवार रात एक मकान में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग की ऊंची लपटें देखकर स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते कार्रवाई होने से आग को आसपास के मकानों तक फैलने से रोक लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया।

घटना की जानकारी मिलते ही इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और प्रभावित परिवार को हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। फायर ब्रिगेड अधिकारियों के अनुसार रविवार रात करीब 9:15 बजे फूटी कोठी स्थित शराब दुकान के समीप एक मकान में आग लगने की सूचना कंट्रोल रूम को मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया। आग की तीव्रता को देखते हुए अतिरिक्त दमकल वाहन भी बुलाए गए, जिसके बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के समय मकान में पांच लोग मौजूद थे। दमकल और स्थानीय लोगों की सतर्कता से चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के दौरान कुछ देर के लिए इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, लेकिन राहत दल की तत्परता से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट सहित अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

पिकनिक मनाने गए थे, पानी बढ़ने से फंस गए

चोरल की बाढ़ में फंसे 3 युवक, बेल्ट-रुमाल के सहारे निकाला

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

चोरल नदी में रविवार शाम करीब 6 बजे बड़वाह से 5 किमी दूर सिद्धवरकूट रोड पर चौड़ापाट के पास बड़ा हादसा टल गया। यहां पिकनिक मनाने आए युवक चोरल नदी के बीच में बैठे हुए थे।

लगातार चोरल इलाके में बारिश होने से नदी अचानक पानी बढ़ जाने से तीनों युवक बीच नदी में फंस गए। उनकी किस्मत अच्छी रही थी कि लोगों ने उन्हें देख लिया। फिर स्थानीय युवाओं ने बेल्ट-रुमाल के सहारे रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई। यदि कुछ देरी हो जाती तो वे बह जाते। जानकारी के अनुसार तीनों युवक इंदौर के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले थे। इसमें से एक का नाम राहुल निवासी आजाद नगर आया है। वे यहां पार्टी मनाने आए थे, लेकिन तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। गनीमत रही कि वहां से गुजर रहे स्थानीय युवाओं ने समझदारी दिखाई और अपनी जान पर खेलकर तीनों को सही-सलामत बाहर निकाल लिया। चोरल में अचानक बढ़ा पानी घटना को अपनी आंखों से देखने वाले शिव मुवेल और अनिल केवट ने बताया कि वे शाम को चौड़ापाट से गुजर रहे थे, तभी उन्हें नदी की तरफ से बचाओ-बचाओ की आवाजें सुनाई दीं। जब उन्होंने रुककर देखा तो तीन युवक पानी के तेज बहाव के बीच फंसे हुए थे और चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज सुनकर सड़क से गुजर रहे दूसरे राहगीर भी वहां रुक गए।

कार्यालय पताः 201, दूसरी मंजिल, इंदौर प्रेस क्लब परिसर, एम.जी. रोड, (जिला न्यायालय के सामने), इंदौर (म.प्र.),
स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक नवीन गलकर द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं ए-119, वीणा नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादकः नवीन गलकर, मो. 9009919948